गरवी गुजरात

RNI No.: UPHIN/25/A1697

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 156
दि. 05.10.2025,
रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : ASHWANI KUMAR Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

संक्षिप्त समाचार

प्रधानमंत्री ने तिरुप्पुर कुमारन और सुब्रमण्य शिवा को उनके स्मृति दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की दो महान विभूतियों - तिरुप्पुर कुमारन और सुब्रमण्य शिवा - को उनके स्मृति दिवस पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने एक्स पर अलग-अलग पोस्ट में कहा:"इस दिन, हम भारत माता के दो महान सपूतों, तिरुप्पुर कुमारन और सुब्रमण्य शिवा को याद करते हैं और उन्हें नमन करते हैं। दोनों ही महान राज्य तमिलनाडु से थे और उन्होंने भारत की स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।

भारत-ब्रिटेन के रिश्तों को लगेंगे पंख, पीएम मोदी के न्यौते पर भारत आ रहे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यौते पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर 8-9 अक्टूबर 2025 को भारत का दौरा करेंगे. यह ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टार्मर की भारत की पहली आधिकारिक यात्रा होगी. 9 अक्टूबर को मुंबई में दोनों प्रधानमंत्री भारत-ब्रिटेन 'कम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप' की प्रगति की समीक्षा करेंगे. यह साझेदारी 'विजन 2035' के तहत है, जिसमें अगले 10 साल के लिए व्यापार और निवेश, टेक्नोलॉजी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु और ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा और जन-जन के रिश्तों जैसे कई क्षेत्रों में काम करने की रूपरेखा तय की गई है.

दोनों नेता 'इंडिया-यूके कम्प्रिहेंसिव इकॉनमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट (CETA)' के अवसरों पर उद्योगपतियों और व्यापार जगत से भी चर्चा करेंगे. इसके अलावा वे क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार-विमर्श करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री स्टार्मर मुंबई में होने वाले ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के 6वें संस्करण में भी शामिल होंगे और मुख्य भाषण देंगे. वहां वे उद्योग विशेषज्ञों, नीतिनिर्माताओं और नवाचारकों से भी मिलेंगे. यह दौरा 23-24 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी के ब्रिटेन दौरे से बनी गति और सकारात्मक माहौल को आगे बढ़ाएगा. दोनों देशों के बीच यह संवाद न केवल आर्थिक और तकनीकी सहयोग को नई दिशा देगा, बल्कि एक आधुनिक, मजबूत और भविष्य उन्मुख साझेदारी की नींव को और मजबूत करेगा.

भारत-ब्रिटेन के बीच क्वांटम कंप्यूटिंग पर समझौता

क्वांटम कंप्यूटिंग और जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जलवायु परिवर्तन के हिसाब से फसलें उगाने में किसानों की मदद करने के लिए इंपीरियल कॉलेज लंदन और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बॉम्बे के बीच एक समझौता हुआ है. यह समझौता अगले सप्ताह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टार्मर की मुंबई यात्रा से पहले हुआ है. यह परियोजना 'भारत-यूके टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव. (टीएसआई) का हिस्सा है, जो क्वांटम तकनीक पर आधारित है. इसका उद्देश्य मृदा सूक्ष्मजीवों को बेहतर बनाना और सूखे व जलवायु परिवर्तन से प्रभावित क्षेत्रों में फसलों की रक्षा के नए तरीके खोजना है.

पिछले वर्ष हस्ताक्षरित 'भारत-यूके टीएसआई' मंगलवार को मुंबई में शुरू हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट

समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट निर्देश, 100 वर्ग मीटर से बड़े भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग जरूरी

लखनऊ : (जीएनएस)। प्रदेश में सौ वर्ग मीटर से बड़े भवनों में अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह निर्देश दिया है। कहा, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए यह कदम निर्णायक साबित होगा। उन्होंने एक अप्रैल से 15 जून तक कुम्हारों को तालाबों से मुफ्त में मिट्टी निकालने की छूट प्रदान किए जाने का निर्देश भी दिया।

योगी आदित्यनाथ ने नमामि गंगे व ग्रामीण जलापूर्ति विभाग (लघु सिंचाई) की समीक्षा बैठक में बढ़ते जल संकट पर चिंता जताई। कहा कि चेक डैम, तालाब व ब्लास्टकूप वर्षा जल को रोककर उसे धीरे-धीरे भूमि में समाहित होने देते हैं। 'एक पेड़ मां के नाम' की तर्ज पर जनांदोलन बनाते हुए चेक डैम, तालाब व ब्लास्टकूप का निर्माण एवं जीर्णोद्धार कराए जाने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 100 वर्ग मीटर से बड़े सभी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। वर्ष 2017 तक प्रदेश में 82 अतिदोहित व 47 क्रिटिकल क्षेत्र थे। राज्य सरकार के प्रयासों से इनकी संख्या में कमी आई। वर्ष 2024 में 50 अतिदोहित व 45 क्रिटिकल क्षेत्र रह गए। इस दिशा में और तेजी लाकर आने वाले वर्षों में इन क्षेत्रों को पूरी तरह सामान्य श्रेणी में लाने का प्रयास किया जाए।

योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में स्थानीय/बरसाती नदी/नालों में 6,448 चेकडैमों का निर्माण किया जा चुका है। प्रत्येक चेकडैम से औसतन 20 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता विकसित होती है। इस प्रकार निर्मित चेकडैमों से कुल 1,28,960 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित हुई है। इसे प्रत्येक वर्ष 10 हजार हेक्टेयर मीटर से अधिक भूजल रिचार्ज हो रहा है। इन प्रयासों से किसान वर्ष में दो से तीन फसल लेने में सक्षम हुए हैं।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने गोवा में राज्य सरकार की 'म्हाजे घर योजना' व विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया

(जीएनएस)।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज गोवा में राज्य सरकार की 'म्हाजे घर योजना' व विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस अवसर पर गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत और केन्द्रीय मंत्री श्रीपद नाइक सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

अपने सम्बोधन में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि आज शुरू हो रही म्हाजे घर योजना सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है बल्कि एक कुशल प्रशासक, संवेदनशील सरकार और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकारों द्वारा सुधारों के लिए की गई मेहनत का परिचायक है। उन्होंने कहा कि लगभग 11 प्रकार के अलग-अलग कानूनी पचड़ों में फंसे हुए गोवा के लाखों नागरिको को उनके मकान का अधिकार देना, एक बहुत बड़े सशक्तिकरण की निशानी है। उन्होंने कहा कि डा. प्रमोद सावंत और उनकी टीम ने एक ही कानून बनाकर सभी

हाउसिंग विसंगतियों को समाप्त कर गोवा की आधी आबादी को फायदा पहुंचाया है। श्री शाह ने कहा कि गोवा सरकार ने घर की मरम्मत के लिए तीन दिन के अंदर अनुमति देना और बिजली और पानी की आपूर्ति को भी सुनिश्चित किया है।

श्री अमित शाह ने कहा कि जब 2014 में श्री नरेन्द्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने सभी राज्यों को प्रेरणा दी कि लोगों की समस्याओं को जानें, उनके दुख को समझें, उन समस्याओं का कानूनी हल निकालें और जरूरी हो तो समाधान के लिए नया कानून लाकर लोगों को उनका अधिकार दें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की उसी प्रेरणा से आज हमारी सभी सरकारें देशभर में काम कर रही हैं और उसी का नतीजा है कि आजादी के 75 साल बाद देश के 60 करोड़ गरीबों को जीवन की सभी आवश्क सुविधाएं मिल गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के 60 करोड़ गरीबों के जीवन में उजियारा भरने का काम किया है।

प्रधानमंत्री ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान को भारत की नारी शक्ति के लिए प्रभावशाली और लाभकारी बनाने के लिए जमीनी स्तर पर काम करने वालों की सराहना की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज उन सभी लोगों के प्रशंसनीय प्रयासों की सराहना की जिन्होंने स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान को भारत की नारी शक्ति के लिए प्रभावशाली और लाभकारी बनाने के लिए जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है।

प्रधानमंत्री ने इस अभियान को जनभागीदारी-जन सहभागिता का एक शानदार उदाहरण बताते हुए इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के सामूहिक कार्य जीवन को बेहतर बनाने और एक स्वस्थ, सशक्त समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण है।

श्री मोदी ने केंद्रीय मंत्री श्री जे.पी. नड्डा द्वारा एक्स पर पोस्ट किए गए एक पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा:

केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने गांधीनगर में राष्ट्रव्यापी वित्तीय जागरूकता अभियान "आपकी पूंजी, आपका अधिकार" लॉन्च किया

(जीएनएस)।

केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान "आपकी पुंजी, आपका अधिकार" का शुभारंभ किया। इस अभियान का शुभारंभ राज्य के वित्त मंत्री श्री कनुभाई देसाई की उपस्थिति में किया गया।

इस कार्यक्रम में डीएफएस के सचिव श्री एम. नागराजू, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक, आईआरडीएआई, सेबी, पीएफआरडीए के पूर्णकालिक सदस्य, भारत सरकार, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और प्रमुख वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।

इस अवसर पर केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस अभियान का एक सरल लेकिन शक्तिशाली संदेश है कि नागरिकों द्वारा बचाया गया प्रत्येक रुपया उन्हें या उनके परिवारों को वापस मिलना चाहिए।

वित्त मंत्री ने कहा कि अदावाकृत जमा, बीमा राशि, लाभांश, म्यूचुअल फंड शेष और पेंशन केवल कागज पर लिखी प्रविष्टियां नहीं हैं, वे सामान्य परिवारों की कड़ी मेहनत से अर्जित बचत का प्रतिनिधित्व करते हैं- ऐसी बचत जो शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और वित्तीय सुरक्षा में सहायक हो सकती है।

इसके अलावा, केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस अभियान के मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में "3ए" - जागरूकता, पहुंच और कार्रवाई- के महत्व पर बल दिया। जागरूकता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक नागरिक और समुदाय को लावारिस संपत्तियों का पता लगाने के बारे में जानकारी हो। पहुंच सरलीकृत डिजिटल उपकरण और ज़िला-स्तरीय पहुंच प्रदान करने पर केंद्रित है। कार्रवाई समयबद्ध और पारदर्शी दावा निपटान पर बल देती है।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये तीनों स्तंभ मिलकर नागरिकों और वित्तीय संस्थानों के बीच की खाई को पाटने, सामुदायिक जागरूकता को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने में मदद करेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति सम्मान और आसानी से अपनी सही बचत को प्राप्त कर सके।

वित्त मंत्री ने हाल ही में चलाए गए केवाईसी और पुनः-केवाईसी अभियानों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, विशेष रूप से गुजरात ग्रामीण बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों की सक्रिय भूमिका की सराहना की और कहा कि इन प्रयासों ने नागरिकों और औपचारिक वित्तीय प्रणाली के बीच संबंध को मजबूत किया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि गांवों और कस्बों में की गई ऐसी पहलों ने यह सुनिश्चित किया है कि लाभार्थी अपनी बचत और अधिकारों से जुड़े रहें, जिससे वर्तमान अभियान की सफलता की मजबूत नींव पड़ी है।

श्रीमती सीतारमण ने सभी संस्थाओं से आग्रह किया कि वे लावारिस वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में इस राष्ट्रव्यापी पहल में समान समर्पण और पहुंच बनाए रखें, ताकि कोई भी नागरिक अपने वैध धन से वंचित न रह जाए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने उन लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी सौंपे, जिन्होंने विभिन्न संस्थानों से अपनी दावारहित जमा राशि को सफलतापूर्वक वापस पा लिया।

इस अवसर पर बोलते हुए, गुजरात के वित्त मंत्री श्री कनुभाई देसाई ने कहा कि गुजरात से इस राष्ट्रव्यापी अभियान का शुभारंभ राज्य के लिए गौरव की बात है और उन्होंने सक्रिय भागीदारी और पहुंच के माध्यम से इसके सफल क्रियान्वयन के लिए पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया।

केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पटना में रबी कार्यशाला एवं कृषि सलाहकार संवाद को संबोधित किया

(जीएनएस)।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बिहार प्रवास के दौरान पटना में आयोजित रबी कार्यशाला एवं कृषि सलाहकार संवाद कार्यक्रम में भाग लिया और कृषि वैज्ञानिकों, सलाहकारों एवं किसानों को संबोधित किया।

अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 'कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा हैं। किसानों की सेवा करना मेरे लिए भगवान की पूजा के समान है।'

श्री चौहान ने कहा कि एक समय था जब भारत अमेरिका से पी.एल.-480 के अंतर्गत लाल गेहूँ आयात करता था, किंतु आज की स्थिति यह है कि देश के भंडार

गेहूँ और चावल से भरे हुए हैं और भारत अन्य देशों को भी अनाज निर्यात कर रहा है। इसमें किसानों की कड़ी मेहनत और कृषि सलाहकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

कृषि मंत्री ने कृषि सलाहकारों की सराहना करते हुए कहा कि यदि सलाहकार न हों तो अनुसंधान प्रयोगशालाओं की उपलब्धियां जमीन तक नहीं पहुँच पाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने कृषि सलाहकारों की जरूरत और मूल्य दोनों को पहचाना है और उनके सम्मान एवं हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

श्री चौहान ने बिहार में दलहन और मक्का उत्पादन की संभावनाओं पर विशेष बल दिया और कहा कि 'दलहन मिशन के माध्यम से देश को दालों में भी आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, और इसमें कृषि सलाहकारों की अहम भूमिका होगी।' उन्होंने हाल ही में मंत्रिमंडल द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (टरढ) में वृद्धि का भी उल्लेख किया।

कार्यक्रम के दौरान श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना' के अंतर्गत उत्पादकता में कमी वाले जिलों को विशेष फोकस में रखा गया है, जिसमें बिहार के भी कई जिले शामिल हैं। इस योजना के तहत 11 विभाग मिलकर सामूहिक रूप से कार्य करेंगे।

राजनीतिक दल मजबूत लोकतंत्र के महत्वपूर्ण हितधारक हैं: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार

चुनाव आयोग ने बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा की

(जीएनएस)।

मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) श्री ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्तों डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ आज पटना में बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव तैयारियों की विस्तृत और व्यापक समीक्षा की।

दो दिवसीय समीक्षा यात्रा के पहले दिन आयोग ने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों अर्थात आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) (लिबरेशन), जनता दल

(यूनाइटेड), लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की और उनसे सुझाव मांगे।

मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने राजनीतिक दलों को मजबूत लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हितधारक बताया और राजनीतिक दलों से चुनाव प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में मतदान और मतगणना एजेंटों की नियुक्ति करके भाग लेने का आ'ान किया।

आयोग ने राजनीतिक दलों को मतदाताओं के साथ मिलकर पूरे दिल से उत्सव की भावना से चुनाव मनाने के लिए प्रोत्साहित किया।

राजनीतिक दलों ने ऐतिहासिक विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने और मतदाता सूचियों को सही करने के लिए आयोग को धन्यवाद दिया और चुनावी प्रक्रियाओं में अपनी आस्था और विश्वास दोहराया।

राजनीतिक दलों ने चुनावों में मतदाताओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सुझाव दिया कि चुनाव छठ त्योहार के तुरंत बाद कराएं जाए और चुनाव यथासंभव कम चरणों में पूरे किए जाएं।

सम्पादकीय

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी की यात्रा तालिबान के किसी नेता की पहली भारत यात्रा

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी की भारत यात्रा से पाकिस्तान का तिलमिलाना स्वाभाविक है क्योंकि उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शिकायत करके मुत्तकी की इसी वर्ष अगस्त में होने वाली भारत यात्रा पर प्रतिबंध लगवाया था। किंतु भारत ने इस प्रतिबंध को खत्म करवाकर विदेश मंत्री मुत्तकी को भारत आने की अनुमति दिलाई। विदेश मंत्री मुत्तकी 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक भारत में रहेंगे किंतु इससे पहले वह रूसी अधिकारियों के निमंत्रण पर 'मास्को फार्मेट' वार्ता में भाग लेने रूस जाएंगे। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान यूएनएससी 1988 तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष है फिर भी वह रूस की मास्को फार्मेट में अफगानिस्तान को हिस्सा लेने से रोक नहीं पाया।

बहरहाल मास्को के बाद मुत्तकी भारत आएंगे। यह तालिबान के किसी नेता की पहली भारत यात्रा होगी। इससे पहले भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दुबई में मुत्तकी से मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान विदेश सचिव मिस्री ने अफगानिस्तान के स्वास्थ्य क्षेत्र और शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए भारत द्वारा की जाने वाली मानवीय सहायता के संदर्भ में बात की थी। उल्लेखनीय है कि भारत ट्रकों से जब अफगानिस्तान को सहायता और खाने की सामग्री भेजना चाहता है तो पाकिस्तान न सिर्फ एतराज करता बल्कि अनाज और दवाइयों को खोलकर नष्ट कर देता था। पाकिस्तान इसके लिए अजीबोगरीब तर्व देता था, कहता था कि भारत को चाहिए अपने ट्रकों को पाकिस्तान के बजाय किसी और रास्ते से भेजे क्योंकि यदि पाकिस्तान के अंदर ट्रकों पर आतंकी हमला हो गया तो भारत की फौज पाकिस्तान पर हमला कर देगी।

पाकिस्तान की इन खुराफातों से तंग आकर ही भारत ने चाबहार बंदरगाह से अफगानिस्तान के लिए मानवीय सहायता सामग्री और बाद में भूवंप के दौरान राहत सामग्री भेजी।

सच तो यह है कि तालिबान आज भी यूएनएससी द्वारा प्रतिबंधित संगठन है। इसलिए तालिबानी नेताओं को विदेश यात्रा की अनुमति नहीं है। यूएनएससी 1988 की एक 15 सदस्यीय समिति है जिसका अध्यक्ष पाकिस्तान है, उसी से अनुमति मिलने पर तालिबान का कोई नेता विदेश यात्रा कर सकता है। किंतु यदि उक्त समिति के एक भी सदस्य ने एतराज कर दिया तो उनको यात्रा रद्द करनी पड़ती है। अगस्त में विदेश मंत्री मुत्तकी की भारत यात्रा पर पाकिस्तान के सदस्य के एतराज के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश मंत्री मुत्तकी से बात की थी। 5 सितम्बर को भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की भारत यात्रा रद्द हो गई है। किंतु सितम्बर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन में भाग लेने न्यूयार्व गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रयास करके यूएनएससी से अनुमति दिलाई। लगता है कि पाकिस्तान की हिम्मत विदेश मंत्री मुत्तकी को मास्को यात्रा रद्द कराने की नहीं हुई क्योंकि पाकिस्तान भी मास्को का सदस्य है। पाकिस्तान को रूस के सामने भी कटोरा परेड करना पड़ती है। इसलिए वह खुलकर मुत्तकी की रूस यात्रा का विरोध नहीं कर पाया और इसी का फायदा उठाकर भारत ने मुत्तकी की भारत यात्रा की बाधा दूर करने में वूटनीतिक सफलता हासिल कर ली।

यह सही है कि कभी पाकिस्तान अफगानिस्तान का मित्र था या तालिबानी प्रवृत्ति का जन्मदाता था किंतु इन दिनों दोनों एक-दूसरे को बर्बाद करने की कसमें खा चुके हैं। भारत के लिए अफगानिस्तान बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत को चाबहार से अफगानिस्तान होते हुए सेंट्रल एशिया तक पहुंच बनाने के लिए काबुल के शासकों का सहयोग और समर्थन चाहिए। भारत इसीलिए अफगानिस्तान के तालिबानी नेताओं से अपने रणनीतिक सम्बंधों को मजबूती देने का प्रयास कर रहा है।

लब्बोलुआब यह है कि पाकिस्तान तालिबान को अपना शत्रु समझता है और वह नहीं चाहता कि उसके दोनों शत्रुओं के बीच मैत्री मजबूत हो, इसीलिए वह विदेश मंत्री मुत्तकी को भारत आने से रोकना चाहता था।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 62,000 करोड़ रुपये से अधिक की युवा-केंद्रित पहलों का शुभारंभ करते हुए कौशल दीक्षांत समारोह को संबोधित किया

भारत ज्ञान और कौशल का देश है, यह बौद्धिक शक्ति हमारी सबसे बड़ी शक्ति है: श्री नरेन्द्र मोदी

आईटीआई न केवल औद्योगिक शिक्षा के प्रमुख संस्थान हैं, बल्कि वे आत्मनिर्भर भारत की कार्यशालाएं भी हैं: प्रधानमंत्री

पीएम-सेतु योजना भारत के युवाओं को दुनिया की कौशल मांगों से जोड़ेगी: श्री नरेन्द्र मोदी

भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी ने अपना पूरा जीवन समाज सेवा और शिक्षा के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया, उनके नाम पर स्थापित किया जा रहा कौशल विश्वविद्यालय उस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम बनेगा: प्रधानमंत्री

युवाओं की ताकत बढ़ने से राष्ट्र की मजबूती होती है: प्रधानमंत्री

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में कौशल दीक्षांत समारोह के दौरान 62,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली विभिन्न युवा-केंद्रित पहलों का शुभारंभ किया। देश भर के आईटीआई से जुड़े लाखों छात्रों और बिहार के छात्रों एवं शिक्षकों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि कुछ वर्ष पहले सरकार ने आईटीआई छात्रों के लिए बड़े पैमाने पर दीक्षांत समारोह आयोजित करने की एक नई परंपरा शुरू की थी। उन्होंने कहा कि आज का दिन उस परंपरा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का समारोह भारत द्वारा कौशल विकास को दी जाने वाली प्राथमिकता का प्रतीक है। उन्होंने शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में देश भर के युवाओं के लिए दो प्रमुख पहलों की शुरूआत की घोषणा की। श्री मोदी ने इस बात का उल्लेख किया कि 60,000 करोड़ रुपये की पीएम सेतु योजना के तहत आईटीआई अब उद्योगों के साथ और अधिक मजबूती से एकीकृत होंगे। उन्होंने कहा कि आज देश भर के नवोदय विद्यालयों और एकलव्य मॉडल स्कूलों में 1,200 कौशल प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया गया है।

श्री मोदी ने कहा कि इस आयोजन की प्रारंभिक योजना विज्ञान भवन में एक दीक्षांत समारोह आयोजित करने की थी। उन्होंने कहा श्री नीतीश कुमार द्वारा इस अवसर को एक विशाल उत्सव में बदलने के प्रस्ताव के साथ यह एक भव्य समारोह - "सुनहरे आभूषणों से सुसज्जित एक 'पिटारे' - में बदल गया। प्रधानमंत्री ने इस बात का उल्लेख किया कि इसी मंच से बिहार के युवाओं के लिए कई योजनाओं और परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। इनमें बिहार में एक नए कौशल प्रशिक्षण विश्वविद्यालय की स्थापना, अन्य विश्वविद्यालयों में सुविधाओं का विस्तार, एक नए युवा आयोग का गठन और हजारों युवाओं को स्थायी सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र जारी करना शामिल है। उन्होंने कहा कि ये पहल बिहार के युवाओं के उज्जवल भविष्य की गारंटी हैं।

श्री मोदी ने बिहार की महिलाओं के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता पर केन्द्रित लाखों बहनों के लिये हाल ही में आयोजित बड़े कार्यक्रम को याद करते हुए कहा कि बिहार में युवा सशक्तीकरण के लिए आज का यह विशाल कार्यक्रम राज्य के युवाओं और महिलाओं के प्रति उनकी सरकार की प्राथमिकता को दर्शाता है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत ज्ञान और कौशल का देश है और यह बौद्धिक शक्ति इसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। जब कौशल और ज्ञान राष्ट्रीय आवश्यकताओं के साथ जुड़ते हैं और उन्हें पूरा करने में योगदान देते हैं तो उनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी की माँग देश की आवश्यकताओं के अनुसार स्थानीय प्रतिभा, स्थानीय संसाधनों, स्थानीय कौशल और स्थानीय ज्ञान को तेजी से आगे बढ़ाने की है। इस मिशन में हजारों आईटीआई की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वर्तमान में आईटीआई लगभग 170 ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। पिछले 11 वर्षों में, 1.5 करोड़ से ज्यादा युवाओं ने इन विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है और विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी योग्यताएँ प्राप्त की हैं। उन्होंने गर्व के साथ कहा कि ये कौशल स्थानीय भाषाओं में प्रदान किए जाते हैं, जिससे बेहतर समझ और सुगमता संभव होती है। इस वर्ष अखिल भारतीय ट्रेड टेस्ट में 10 लाख से ज्यादा छात्रों ने भाग लिया और प्रधानमंत्री को इस कार्यक्रम के दौरान उनमें से 45 से ज्यादा को सम्मानित करने का अवसर मिला।

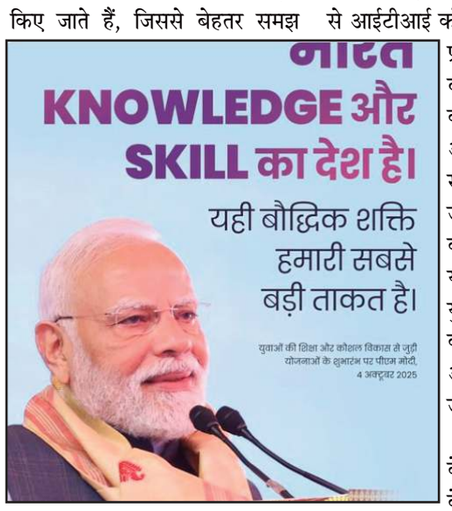

श्री मोदी ने इस अवसर पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि पुरस्कार विजेताओं में से काफी लोग भारत के ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों से हैं। उन्होंने इनमें बेटियों और दिव्यांग साथियों की उपस्थिति का जिक्र करते हुए समर्पण एवं दृढ़ता से अर्जित उनकी सफलता की सराहना की।

प्रधानमंत्री ने कहा "भारत के आईटीआई न केवल औद्योगिक शिक्षा के लिए प्रमुख संस्थान हैं बल्कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण हेतु कार्यशालाओं के रूप में भी काम करते हैं।" उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार आईटीआई की संख्या बढ़ाने और उन्हें निरंतर उन्नत बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। वर्ष 2014 तक देश में केवल 10,000 आईटीआई थे लेकिन पिछले एक दशक में लगभग 5,000 नए आईटीआई स्थापित किए गए हैं। श्री मोदी ने इस बात का उल्लेख किया कि आईटीआई नेटवर्क को वर्तमान उद्योग कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने और अगले दस वर्षों में भविष्य की मांगों का अनुमान लगाने के लिए तैयार किया जा रहा है। इस दिशा में उद्योग और आईटीआई के बीच समन्वय बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने पीएम सेतु योजना शुरू करने की घोषणा की जिससे पूरे भारत में 1,000 से अधिक आईटीआई संस्थान लाभान्वित होंगे। इस पहल के माध्यम से आईटीआई को नई मशीनरी, उद्योग प्रशिक्षण विशेषज्ञों और वर्तमान एवं भविष्य की कौशल मांगों के अनुरूप पाठ्यक्रम के साथ उन्नत किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा "पीएम सेतु योजना भारतीय युवाओं को वैश्विक कौशल आवश्यकताओं से भी जोड़ेगी।"

श्री मोदी ने आज के कार्यक्रम में बिहार के हजारों युवाओं के शामिल होने का उल्लेख करते हुए कहा कि आज की पीढ़ी शायद पूरी तरह से समझ नहीं पाएगी कि दो-ढाई दशक पहले बिहार की शिक्षा व्यवस्था कितनी बदहाल थी। न तो स्कूल ईमानदारी से खोले गए और न ही भर्तियाँ की गईं। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि हर माता-पिता की इच्छा होती है कि उनका बच्चा यहीं पढ़े और आगे बढ़े। लेकिन, मजबूरी में लाखों बच्चों को बिहार छोड़कर बनारस, दिल्ली और मुंबई जैसी जगहों पर पलायन करना पड़ा।

श्री मोदी ने कहा कि जिस पेड़ की जड़ें सड़ चुकी हों, उसे पुनर्जीवित करना एक कठिन काम है, उन्होंने विपक्ष के कुशासन में बिहार की स्थिति की तुलना ऐसे ही एक पेड़ करते हुए कहा कि सौभाग्य से बिहार की जनता ने श्री नीतीश कुमार को शासन की ज़िम्मेदारी सौंपी और गठबंधन सरकार की पूरी टीम ने पटरी से उतरी व्यवस्थाओं को बहाल करने के लिए मिलकर काम किया। आज का कार्यक्रम उस बदलाव की एक झलक पेश करता है।

प्रधानमंत्री ने आज के कौशल दीक्षांत समारोह में बिहार को एक नए कौशल विश्वविद्यालय की सौगात मिलने पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने इस विश्वविद्यालय का नाम भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर रखा है। श्री मोदी ने इस बात का उल्लेख किया भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर ने अपना पूरा जीवन जनसेवा और शिक्षा के विस्तार के लिए समर्पित कर दिया और समाज के सबसे वंचित वर्गों के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। उन्होंने कहा कि उनके सम्मान में नामित कौशल विश्वविद्यालय इसी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम बनेगा।

श्री मोदी ने कहा कि केंद्र और राज्य की उनकी सरकारें बिहार के शैक्षणिक संस्थानों के आधुनिकीकरण के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं। आईआईटी पटना में बुनियादी ढाँचे का विस्तार शुरू हो चुका है और बिहार के कई प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों का आधुनिकीकरण भी शुरू हो गया है। श्री मोदी ने घोषणा की कि एनआईटी पटना का बिहटा परिसर अब प्रतिभाशाली छात्रों के लिए खोल दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि पटना विश्वविद्यालय, भूपेंद्र मंडल विश्वविद्यालय, छपरा स्थित जय प्रकाश विश्वविद्यालय और नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय में नए शैक्षणिक बुनियादी ढाँचे की नींव रखी गई है।

श्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि शैक्षणिक संस्थानों को मजबूत करने के साथ-साथ श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार बिहार के युवाओं पर शिक्षा का आर्थिक बोझ कम करने के लिए भी सक्रिय रूप से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि छात्रों को उच्च शिक्षा की फीस भरने में कोई कठिनाई न हो, इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बिहार सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से छात्रों की मदद कर रही है और अब इस योजना के तहत शिक्षा ऋण को ब्याज मुक्त बनाने का एक बड़ा फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि छात्रों की छात्रवृत्ति राशि 1,800 रुपये से बढ़ाकर 3,600 रुपये कर दी गई है।

प्रधानमंत्री ने कहा, "भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है और बिहार युवाओं के उच्चतम अनुपात वाले राज्यों में से एक है।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जब बिहार के युवाओं की क्षमता बढ़ती है, तो राष्ट्र की शक्ति भी बढ़ती है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बिहार के युवाओं को और सशक्त बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि पिछली विपक्षी सरकारों की तुलना में बिहार के शिक्षा बजट में कई गुना वृद्धि की गई है। आज बिहार के लगभग हर गाँव और बस्ती में एक स्कूल है और इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने हाल ही में बिहार के 19 जिलों में केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय था जब बिहार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल बुनियादी ढांचे का अभाव था, लेकिन आज राज्य में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन हो रहे हैं।

श्री मोदी ने पिछले दो दशकों में बिहार सरकार द्वारा 50 लाख युवाओं को राज्य में ही रोजगार के अवसरों से जोड़ने का ज़िक्र करते हुए, कहा कि हाल के वर्षों में ही बिहार के युवाओं को लगभग 10 लाख स्थायी सरकारी नौकरियाँ प्रदान की गई हैं। उन्होंने शिक्षा विभाग को इसका एक प्रमुख उदाहरण बताया, जहाँ बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्ती चल रही है। उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों में बिहार में 2.5 लाख से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर तो मिले ही हैं, साथ ही शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

श्री मोदी ने कहा कि बिहार सरकार अब नए लक्ष्यों के साथ काम कर रही है, और राज्य का लक्ष्य अगले पाँच वर्षों में रोजगार के दोगुने अवसर पैदा करना है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि उनका संकल्प स्पष्ट है- बिहार के युवाओं को बिहार में ही रोजगार और काम मिलना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार के युवाओं के लिए यह दोहरे बोनस का समय है। उन्होंने देश भर में चल रहे जीएसटी बचत उत्सव का ज़िक्र किया और बताया कि उन्हें बाइक और स्कूटर पर जीएसटी कम होने से बिहार के युवाओं में खुशी की खबर मिली है। कई युवाओं ने तो धनतेरस पर ये खरीदारी करने की योजना भी बना ली है। श्री मोदी ने बिहार और देश के युवाओं को उनकी ज्यादातर जरूरी चीजों पर जीएसटी कम होने पर बधाई दी।

प्रधानमंत्री ने कहा, "जैसे-जैसे कौशल बढ़ता है, राष्ट्र आत्मनिर्भर बनता है, निर्यात बढ़ता है और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं।"

टीईसी ने आईआईआईटी नया रायपुर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

टीईसी ने अगली पीढ़ी की दूरसंचार प्रौद्योगिकियों और मानकों को आगे बढ़ाने के लिए आईआईआईटी नया रायपुर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

वैश्विक दूरसंचार मानकों और मंचों में भारत की उपस्थिति को मजबूत करने के लिए सहयोग

(जीएनएस)।

दूरसंचार विभाग (डीओटी), भारत सरकार की तकनीकी शाखा, दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र (टीईसी) ने अगली पीढ़ी की दूरसंचार प्रौद्योगिकियों में शोध, नवाचार और मानकीकरण को संयुक्त रूप से आगे बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) नया रायपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

यह महत्वपूर्ण साझेदारी दूरसंचार मानकीकरण में टीईसी के राष्ट्रीय नेतृत्व को आईआईआईटी नया रायपुर की शैक्षणिक और शोध उत्कृष्टता के साथ जोड़ती है, जिससे वैश्विक दूरसंचार नवाचार में भारत की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए एक सहयोगात्मक ढांचा तैयार होता है।

सहयोग के प्रमुख क्षेत्र

ओपन आरएएन और नेटवर्क डिसएग्रीगेशनः ओपन इंटरफेस, मॉड्यूलर आर्किटेक्चर, वर्चुअलाइजेशन और विक्रेता इंटरऑपरेबिलिटी का विकास।

संज्ञानात्मक रेडियो और स्पेक्ट्रम साझाकरणः सह-अस्तित्व ढांचे पर अनुसंधान और डब्ल्यूआरसी-27 एजेंडा मदों के साथ अनुरूप अध्ययन।

5G / 6G / आईओटी फ्रेमवर्कः भविष्य की नेटवर्क पीढ़ियों के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों और परीक्षण वातावरण पर संयुक्त शोध कार्यक्रम।

मानकीकरण योगदानः आईटीयू-टी अध्ययन समूहों और टीईसी के राष्ट्रीय कार्य समूहों में सहयोगात्मक भागीदारी।

भारत-विशिष्ट परीक्षण रूपरेखाः भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के अनुरूप मानकों और अंतर-संचालनीयता समाधानों का विकास।

इस सहयोग से वैश्विक दूरसंचार मानकों और अंतर्राष्ट्रीय नीति मंचों में भारत की भागीदारी उल्लेखनीय रूप से मजबूत होने की उम्मीद है। संयुक्त

शोध परीक्षणों और वास्तविक-विश्व सहयोग को बढ़ावा देकर, यह उभरती संचार प्रौद्योगिकियों में नवाचार को गति देगा। इस साझेदारी का उद्देश्य भारत की विविध संपर्क आवश्यकताओं के अनुकूल किफायती, अंतर-संचालनीय और विक्रेता-तटस्थ समाधान विकसित करके डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देना भी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह देश को दूरसंचार विकास की अगली के लिए तैयार करने में मदद करेगा, जिसमें 6G नेटवर्क और उन्नत आईओटी अनुप्रयोगों का आगमन भी शामिल है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि भारत वैश्विक डिजिटल परिवर्तन में अग्रणी बना रहे।

यह सहयोग दूरसंचार प्रौद्योगिकियों में स्वदेशी शोध, डिजाइन और विकास को बढ़ावा देकर भारत के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को भी आगे बढ़ाएगा। घरेलू विशेषज्ञता का लाभ उठाकर और भारत-विशिष्ट मानकों और परीक्षण ढाँचों का निर्माण करके, यह साझेदारी देश की आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगी और महत्वपूर्ण संचार अवसंरचना में आयातित समाधानों पर निर्भरता को कम करेगी।

टीईसी के बारे में

दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र (टीईसी), भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (डीओटी) की तकनीकी शाखा है। टीईसी भारत में दूरसंचार उपकरणों और नेटवर्क के लिए तकनीकी मानक, विनिर्देश और परीक्षण आवश्यकताएँ तैयार करता है, जिससे अंतर-संचालनीयता, गुणवत्ता और वैश्विक सर्वोत्तम विधियों के साथ सरेखण सुनिश्चित होता है।

आईआईआईटी नया रायपुर के बारे में

अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), नया रायपुर, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में उन्नत शोध और नवाचार में संलग्न एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। यह संस्थान भारत के डिजिटल परिवर्तन हेतु प्रौद्योगिकी विकास, कौशल निर्माण और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उद्योग और सरकार के साथ मिलकर काम करता है।

भारत-सिंगापुर @60: विकास एवं सहभागिता के लिए साझेदारी

(जीएनएस)।

भारत और सिंगापुर के बीच राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर 04 अक्टूबर 2025 को सिंगापुर में "भारत-सिंगापुर @60: विकास एवं सहभागिता के लिए साझेदारी" नामक व्यावसायिक सत्र का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन फिक्की, सीआईआई और एसोचैम द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने इसमें मुख्य भाषण दिया तथा पिछले छह दशकों में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों में हुई परिवर्तनकारी प्रगति की सराहना की। उन्होंने विश्वास एवं पारस्परिक सम्मान पर आधारित गहन द्विपक्षीय संबंधों की आशाजनक संभावनाओं, तथा विशेष रूप से स्थिरता, डिजिटलीकरण, कौशल विकास, स्वास्थ्य सेवा, उन्नत विनिर्माण और कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में व्यापक सहयोग पर चर्चा की।

सुश्री गान सिओ हुआंग, राज्य मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सिंगापुर गणराज्य ने दो देशों के बीच मजबूत आर्थिक एवं जनसंपर्क आधारित व्यापक एवं लंबे समय से चल रहे संबंधों की पुष्टि की। उन्होंने भारत के साथ व्यापार, निवेश एवं नवाचार-संचालित सहयोग को मजबूत बनाने के लिए सिंगापुर के दृष्टिकोण पर व्यावहारिक जानकारी प्रदान की।

इस सत्र में भारत और सिंगापुर दोनों देशों के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, उद्योग जगत के दिग्गजों और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में मजबूत आर्थिक संबंधों पर बल दिया गया तथा दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसरों पर प्रकाश डाला गया, जिसमें प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, हरित ऊर्जा एवं कौशल विकास, औद्योगिक पार्क, अवसंरचना आदि क्षेत्रों में नए युग के अवसरों के लाभ शामिल हैं।

व्यावसायिक सत्र का समापन नेटवर्किंग लंच के साथ हुआ जिसमें प्रतिभागियों के बीच गहन सहभागिता विकसित हुई तथा ठोस व्यावसायिक परिणामों का मार्ग प्रशस्त हुआ।

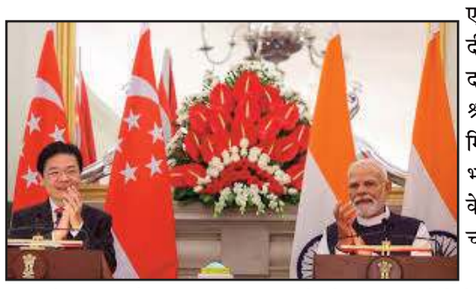

गोलमेज सम्मेलन के दौरान, सहयोग के अवसरों का पता लगाने के लिए अग्रणी वैश्विक निवेशकों एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की गईं:

सेम्बकॉर्प के समूह अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री वोंग किम यिन ने नवीकरणीय ऊर्जा परिवर्तन, हरित हाइड्रोजन की क्षमता एवं कौशल विकास पर चर्चा की।

केपेल कॉर्पोरेशन के सीईओ श्री लोह चिन हुआ ने रियल एस्टेट, अपशिष्ट से ऊर्जा और डिजिटल कनेक्टिविटी में सहयोगी परियोजनाओं पर चर्चा की।

ब्लैकस्टोन सिंगापुर के चेयरमैन श्री गौतम बनर्जी ने प्राइवेट इक्विटी एशिया के प्रमुख श्री अमित दीक्षित और प्राइवेट इक्विटी दक्षिण पूर्व एशिया के प्रमुख श्री अरविंद कृष्णा के साथ मिलकर ब्लैकस्टोन के बढ़ते भारत पोर्टफोलियो पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक अनुवर्ती चर्चा की।

टेक्सास पैसिफिक ग्रुप (टीपीजी) के अध्यक्ष श्री जिम कूल्टर ने भारत के उच्च विकास वाले निवेश क्षेत्रों में अवसरों पर विचार व्यक्त किया।

लखनऊ मुंशीपुलिया में हुआ भव्य परिवार मिलन समारोह

राज्य महिला आयोग अध्यक्ष बबीता सिंह और सदस्य अंजू प्रजापति ने की शिरकत

लखनऊः राजधानी लखनऊ के मुंशीपुलिया स्थित आरोही आर्केड में रविवार को परिवारिक एकता, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक मूल्यों को सशक्त करने के उद्देश्य से भव्य परिवार मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए।

मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती बबीता सिंह ने शिरकत कर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्य महिला आयोग की सदस्य अंजू प्रजापति भी उपस्थित रहीं।

परिवार ही समाज की नींव : बबीता सिंह

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बबीता सिंह ने कहा कि 'परिवार समाज की सबसे मजबूत इकाई है। जब परिवारिक एकता सशक्त होती है, तो समाज और राष्ट्र दोनों मजबूत बनते हैं।'

उन्होंने महिला सुरक्षा, शिक्षा और आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए कहा कि हर परिवार को बेटियों को शिक्षित कर उन्हें आत्मविश्वास से आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए।

महिला सशक्तिकरण के लिए पारिवारिक मूल्य जरूरी : अंजू प्रजापति

राज्य महिला आयोग की सदस्य अंजू प्रजापति ने अपने संबोधन में कहा, 'महिला सशक्तिकरण तभी संभव है जब परिवारिक संस्कार और परंपराएं मजबूत हों। ऐसे आयोजनों से समाज में सामंजस्य और आपसी सहयोग की भावना बढ़ती है।'

उन्होंने सभी से आग्रह किया कि समाज के हर वर्ग को मिलकर महिलाओं और बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए काम करना चाहिए।

सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने बांधा समां

समारोह के दौरान बच्चों से लेकर वरिष्ठजनों तक ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, नृत्य, गीत और विचार गोष्ठी ने माहौल को जीवंत बना दिया।

आयोजन की जिम्मेदारी राघव मिश्र, रिया मिश्र, वासु प्रजापति, इंजीनियर सिद्धार्थ प्रजापति और मोनू गुप्ता ने संभाली।

अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया।

RNI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR

पश्चिम रेलवे मुंबई सेंट्रल-साबरमती और साबरमती-गुड़गांव के बीच दो (वनवे स्पेशल) ट्रेनें चलाएगी

मुंबई, पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को समायोजित करने एवं उनकी यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से मुंबई सेंट्रल-साबरमती और साबरमती-गुड़गांव स्टेशनों के बीच विशेष किराए पर दो वनवे स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है:

1. ट्रेन संख्या 09153 मुंबई सेंट्रल-साबरमती सुपरफास्ट स्पेशल [02 फेरे]

ट्रेन संख्या 09153 मुंबई सेंट्रल-साबरमती सुपरफास्ट स्पेशल मुंबई सेंट्रल से 10:30 बजे प्रस्थान करेगी और उसी दिन 17:20 बजे साबरमती पहुँचेगी। यह ट्रेन 5 और 6 अक्टूबर, 2025 को चलेगी।

यह ट्रेन बोरीवली, वापी, सूरत और वडोदरा स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में एक्जीक्यूटिव चेयर कार और एसी चेयर कार कोच होंगे।

2. ट्रेन संख्या 09401 साबरमती-गुड़गांव सुपरफास्ट स्पेशल [02 फेरे]

ट्रेन संख्या 09401 साबरमती-गुड़गांव सुपरफास्ट स्पेशल साबरमती से 17:30 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 08:25 बजे गुड़गांव पहुँचेगी। यह ट्रेन 5 और 6 अक्टूबर, 2025 को चलेगी।

यह ट्रेन महेसाणा, पालनपुर, आबू रोड, मारवाड़ जं., अजमेर, जयपुर, अलवर और रेवाड़ी स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में एक्जीक्यूटिव चेयर कार और एसी चेयर कार कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 09153 एवं 09401 की बुकिंग सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू है। ट्रेनों के ठहराव, संरचना और समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www. enquiry. indianrail. gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

गैर-फास्टैग उपयोगकर्ताओं के लिए टोल प्लाजा पर डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने हेतु नया उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह नियम

राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) (तृतीय संशोधन) नियम, 2025, 15 नवंबर, 2025 से प्रभावी होंगे

(जीएनएस)। डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने और गैर-फास्टैग उपयोगकर्ताओं के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपयोगकर्ता शुल्क प्लाजा पर नकद लेनदेन को समाप्त करने के एक महत्वपूर्ण कदम में, भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह का निर्धारण) नियम, 2008 में संशोधन किया है। नए नियम के तहत, वैध, कार्यात्मक फास्टैग के बिना शुल्क प्लाजा में प्रवेश करने वाले वाहनों से लागू उपयोगकर्ता शुल्क का दोगुना शुल्क लिया जाएगा, यदि शुल्क का भुगतान नकद में किया जाता है। ऐसे उपयोगकर्ता जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) के माध्यम से शुल्क का भुगतान करना चुनते हैं, उनसे उस श्रेणी के वाहन के लिए लागू उपयोगकर्ता शुल्क का केवल 1.25 गुना शुल्क लिया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी वाहन को वैध फास्टैग के माध्यम से 100 रुपये का उपयोगकर्ता शुल्क देना है, तो नकद में भुगतान करने पर शुल्क 200 रुपये और यूपीआई के माध्यम से भुगतान करने पर 125 रुपये होगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण एवं संग्रह) नियम, 2008 में नवीनतम संशोधन कुशल टोल संग्रहण हेतु प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने और टोल प्लाजा पर भीड़भाड़ कम करने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। संशोधित नियम डिजिटल भुगतान को अपनाने को प्रोत्साहित करेंगे, टोल संचालन में पारदर्शिता बढ़ाएंगे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर समग्र उपयोगकर्ता अनुभव में सुधार लाएंगे।

खान मंत्रालय ने 1,500 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण प्रोत्साहन योजना के लिए दिशा-निर्देश जारी किए

योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन विंडो अब कार्यशील

(जीएनएस)। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 03.09.2025 को महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने हेतु 1,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी मिलने के बाद, खान मंत्रालय ने उक्त प्रोत्साहन योजना के कार्यान्वयन हेतु 02.10.2025 को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों में पुनर्चक्रण प्रणालियों के लिए सांकेतिक परिव्यय, प्रोत्साहन आवंटन की कार्यप्रणाली, आवेदन, मूल्यांकन और संवितरण प्रक्रियाएँ, संस्थागत तंत्र और कार्यनिष्पादन समीक्षा सहित योजना के तौर-तरीके बताए गए हैं। उद्योग और अन्य संबंधित हितधारकों के साथ विस्तृत परामर्श के बाद इन दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिया गया है।

प्रोत्साहन योजना राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का एक प्रमुख घटक है, और इसका उद्देश्य देश में द्वितीयक स्रोतों से महत्वपूर्ण खनिजों के पृथक्करण और उत्पादन के लिए पुनर्चक्रण क्षमता विकसित करना है। पात्र फीडस्टॉक स्रोत ई-कचरा, प्रयुक्त लिथियम-आयन बैटरी (एलआईबी), और अन्य स्क्रैप सामग्री हैं। अपेक्षित लाभार्थी बड़े और स्थापित पुनर्चक्रणकर्ता, और छोटे और नए पुनर्चक्रणकर्ता (स्टार्ट-अप सहित) दोनों होंगे। यह योजना नई इकाइयों में निवेश के साथ-साथ क्षमता विस्तार / आधुनिकीकरण और मौजूदा इकाइयों के विविधीकरण पर लागू होगी। योजना प्रोत्साहन पुनर्चक्रण मूल्य श्रृंखला के लिए होगा जो महत्वपूर्ण खनिजों के वास्तविक निष्कर्षण में है, न कि केवल 'ब्लैक मास' उत्पादन में शामिल मूल्य श्रृंखला के लिए।

ब्लैक मास उपयोग की गई लिथियम-आयन बैटरियों से प्राप्त एक उप-उत्पाद है, जिसमें लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, मैंगनीज और ग्रेफाइट जैसी मूल्यवान धातुएँ होती हैं। बैटरी रीसाइक्लिंग के दौरान बैटरियों को यांत्रिक रूप से कुचलकर और संसाधित करके यह "ब्लैक मास" प्राप्त किया जाता है।

विस्तृत दिशा-निर्देश जारी होने के बाद, यह योजना अब 02.10.2025 से छह (6) महीने की अवधि के लिए, यानी 01.04.2026 तक, आवेदन के लिए खुली है। योजना के दिशानिर्देश और आवेदन करने का लिंक खान मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

यूआईडीएआई ने 7-15 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए आधार बायोमेट्रिक अपडेट प्रक्रिया के लिए शुल्क माफ किया, जिससे करीब 6 करोड़ बच्चों को लाभ होगा

एमबीयू शुल्क में छूट 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगी और एक वर्ष तक लागू रहेगी

आधार में निःशुल्क बायोमेट्रिक अपडेट की सुविधा से बच्चों की शिक्षा, छात्रवृत्ति और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजनाओं तक पहुँच आसान होगी

(जीएनएस)। जनहित में उठाए गए एक बड़े कदम के तहत, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (एमबीयू-1) के सभी शुल्क माफ कर दिए हैं। इस कदम से करीब 6 करोड़ बच्चों को लाभ मिलने की उम्मीद है। उक्त आयु वर्ग के लिए एमबीयू शुल्क में छूट 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो चुकी है और यह सुविधा एक वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगी।

पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चे का, आधार के लिए नामांकन उसकी तस्वीर, नाम, जन्मतिथि, लिंग, पता और जन्म प्रमाण पत्र प्रदान करके किया जाता है। पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों के आधार नामांकन के लिए उनके उंगलियों के निशान और आँखों की पुतलियों के बायोमेट्रिक्स नहीं लिए जाते, क्योंकि वे उस आयु तक परिपक्व नहीं होते।

इसलिए, मौजूदा नियमों के अनुसार, बच्चे के पाँच वर्ष की आयु पूरी करने पर उसके आधार में उंगलियों के निशान, आँखों की पुतलियों और तस्वीर को अनिवार्य रूप से अपडेट करना जरूरी है। इसे पहला अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (एमबीयू) कहा जाता है। इसी तरह, 15 वर्ष की आयु होने पर बच्चे को एक बार फिर बायोमेट्रिक्स अपडेट कराना जरूरी होता है, जिसे दूसरा एमबीयू कहा जाता है।

इस प्रकार, पहला और दूसरा एमबीयू, यदि क्रमशः 5-7 वर्ष और 15-17 वर्ष की आयु के बीच कराया जाता है, तो यह निःशुल्क होता है। इसके बाद, प्रति एमबीयू 125 रुपये का निर्धारित शुल्क लिया जाता है। इस फैसले से अब 5-17 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए एमबीयू प्रभावी रूप से निःशुल्क है।

अपडेट किए गए बायोमेट्रिक के साथ आधार, जीवन में कई प्रक्रियाओं को आसान बनाता है और स्कूल में प्रवेश, प्रवेश परीक्षाओं के लिए पंजीकरण, छात्रवृत्ति का लाभ उठाने, डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) योजनाओं आदि जैसी सेवाओं, जहाँ भी यह लागू होता है, उनका लाभ उठाने में आधार का उपयोग सरल बनाता है। माता-पिता/अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बच्चों/आश्रितों के बायोमेट्रिक्स को प्राथमिकता के आधार पर आधार में अपडेट करें।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री श्रीपद येसो नाइक ने गोवा जल आपूर्ति के लिए इरेडा की 45

(जीएनएस)। माननीय केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री श्रीपद येसो नाइक ने आज इरेडा की सीएसआर पहल के तहत उत्तरी गोवा जिले में एक जल पंपिंग स्टेशन पर 45 किलोवाट ऑन-ग्रिड सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना का उद्घाटन किया।

वार्षिक रूप से लगभग 60,000 यूनिट बिजली उत्पादन की उम्मीद के साथ यह परियोजना पंपिंग लोड के शत-प्रतिशत सौर ऊर्जा प्राप्त करेगी। इसका उद्देश्य यह प्रदर्शित करना है कि अक्षय ऊर्जा कैसे सार्वजनिक जल वितरण प्रणालियों को स्थायी रूप से शक्ति प्रदान कर सकती है।

एक संदेश में, इरेडा के सीएमडी श्री प्रदीप कुमार दास ने कहा, 'यह पहल वित्त पोषण से परे और सामुदायिक विकास में स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार करने की इरेडा की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। जल पम्पिंग स्टेशनों जैसी सार्वजनिक सेवाओं में सौर ऊर्जा का उपयोग देश भर में सतत ऊर्जा परिवर्तन के लिए एक अनुकरणीय मॉडल बन सकता है।'

इस कार्यक्रम में इरेडा की सीएसआर टीम, गोवा पेयजल विभाग और स्थानीय अधिकारी उपस्थित थे।

6 से 9 अक्टूबर तक गोझरिया स्थित रेलवे फाटक नं. 78 बंद रहेगा

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल पर महेसाणा-गोझरिया हाईवे के बीच गोझरिया स्थित रेलवे फाटक नं. 78 आंबलियासन-विजापुर रेलवे लाइन गेज परिवर्तन परियोजना के अंतर्गत चेक रेल एवं रोड अलाइनमेंट पर डामर कार्य के चलते 6 अक्टूबर 2025 से 9 अक्टूबर 2025 तक (4 दिन) बंद रहेगा। सड़क उपयोगकर्ता इस अवधि के दौरान गांधीनगर-गोझरिया-विसनगर हाईवे स्थित रेलवे फाटक नं. 77 से आवागमन कर सकते हैं।

25,000 से $21 बिलियन साम्राज्य तक: वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में टॉरेंट ग्रुप संस्थापक स्व. श्री यू.एन. मेहता की प्रेरणादायक यात्रा का उत्सव

- स्व. श्री यू.एन. मेहताः भारत में फार्मा और पावर सेक्टर के अग्रणी, जिन्होंने बनाया एक कॉर्पोरेट दिग्गज और एक अमूल्य उदारवादी विरासत
- वीजीआरसी नॉर्थ गुजरात में सम्मानः स्व. श्री यू.एन. मेहता जैसे दूरदर्शी उद्यमियों को सलाम, जिन्होंने बदल दी भारत की उद्योग और विकास की कहानी

गांधीनगर, 4 अक्टूबरः गुजरात की पवित्र धरती ने अनेक विभूतियों को जन्म दिया है, जिन्होंने भारत की प्रगति की दिशा तय की। इन्हीं में से एक हैं श्री उत्तमभाई नथालाल मेहता (14 जनवरी, 1924 - 31 मार्च, 1998) जो टॉरेंट ग्रुप के संस्थापक और भारतीय उद्योग जगत के उज्ज्वल चमकता सितारा हैं। उन्होंने उस समय दवाओं का उत्पादन शुरू किया, जब भारत जीवनरक्षक दवाओं के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर था। केवल यही नहीं, बिजली उत्पादन और वितरण के क्षेत्र में भी उन्होंने वैश्विक मानकों वाली परियोजनाएँ खड़ी कीं और भारत को गहरे बिजली संकट से बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई। श्री मेहता का जीवन गुजरात की उस उद्यमशीलता का प्रतीक है, जिसने न केवल राज्य, बल्कि पूरे देश को आत्मनिर्भरता और समृद्धि की राह दिखाई।

एक सामान्य युवक से उद्योग जगत में चमकता सितारा बनने की कहानी

उत्तर गुजरात के बनासकांठा जिले के छोटे से गाँव मेमदपुर में जन्मे श्री यू.एन. मेहता का जीवन इसी भावना का जीवंत उदाहरण है। अत्यंत साधारण परिवार में जन्मे और मात्र दो वर्ष की आयु में माता का साया खो

देने वाले इस बालक ने कभी हार नहीं मानी। संघर्षों के बीच उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई का रुख किया। वहाँ विल्सन कॉलेज से केमिस्ट्री में स्नातक की डिग्री प्राप्त की जो उनकी आगे की औद्योगिक यात्रा के लिए मजबूत नींव साबित हुई।

परिस्थितियाँ कठिन थीं, लेकिन हौसले भी बुलंद थे। आर्थिक अभावों के चलते उच्च शिक्षा का उनका सपना अधूरा रह गया, फिर भी उन्होंने 1944 में सरकारी नौकरी कर अपने जीवन की नई शुरुआत की। जल्द ही उन्होंने 1945 से 1958 तक स्विस फार्मा कंपनी 'सैंडोज' में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कार्य किया। यहीं से उन्होंने औषधि उद्योग की बारीकियाँ सीखीं और एक दिन अपना कुछ करने का स्वप्न देखा।

साहस, संकल्प और दूरदर्शिता से उद्योग जगत में हुए प्रसिद्ध श्री यू.एन. मेहता

1959 में श्री यू.एन. मेहता ने साहस और दूरदर्शिता का परिचय देते हुए मात्र 25,000 रुपये की पूँजी से अहमदाबाद में 'ट्रिनिटी लेबोरेट्रीज' (अब टॉरेंट फार्मा) की स्थापना की। यह उस दौर की बात है जब भारत विदेशी दवाओं पर निर्भर था और देश में फार्मा उत्पादन की कल्पना भी कठिन मानी जाती थी। लेकिन गुजरात की धरती पर जन्मे इस कर्मयोगी ने यह असंभव कार्य संभव कर दिखाया।

जीवन ने उन्हें बार-बार परखा। 39 वर्ष की आयु में दवा के दुष्प्रभाव से मानसिक बीमारी, 53 वर्ष में दुर्लभ प्रकार का कैंसर, और 62 वर्ष में हृदय रोग के कारण बाईपास सर्जरी जैसी गंभीर परिस्थितियाँ सामने आईं। उनका पहला व्यावसायिक प्रयास भी असफल रहा, और उन्हें अपने गाँव लौटना पड़ा। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपने अटूट आत्मविश्वास के साथ वे फिर उठ खड़े हुए। 48 वर्ष की आयु में वो पुनः सफलता के शिखर तक पहुँच गए और गुजरात को दिया एक ऐसा औद्योगिक अग्रणी जिसने देश को आत्मनिर्भर औषधि निर्माण की दिशा दिखाई।

दूरदर्शिता से शुरू हुई टॉरेंट समूह की सफलता की यात्रा

1968 में जब भारत का औषधि उद्योग बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नियंत्रण में था, तब श्री यू.एन. मेहता ने अपनी असाधारण दूरदृष्टि और साहस के साथ मनोचिकित्सा संबंधी दवाओं के निर्माण और विपणन की पहल की। यह कदम उस दौर में किसी भी भारतीय उद्यमी के लिए जोखिमपूर्ण था, परंतु श्री मेहता ने इसे देश की आवश्यकता और आत्मनिर्भरता के संकल्प के रूप में अपनाया। उनकी यही नवोन्मेषी सोच और 'नीश मार्केटिंग' रणनीति टॉरेंट समूह की सशक्त नींव बनी, जिसने आगे चलकर स्वास्थ्य, ऊर्जा और खेल जैसे अनेक क्षेत्रों में अपनी उत्कृष्टता का परचम लहराया। आज टॉरेंट समूह का बाजार मूल्य 31 मार्च 2025 तक 21.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुँच चुका है। टॉरेंट समूह आज गुजरात की उस नवाचार-प्रधान औद्योगिक संस्कृति का प्रतीक है, जो परिश्रम, दृष्टि और सामाजिक उत्तरदायित्व को साथ लेकर चलती है।

सेवा को समर्पित जीवन, संस्कारों से संवरती विरासत

श्री मेहता केवल एक सफल उद्योगपति नहीं, बल्कि संवेदनशील शख्सियत हैं।

मॉयल ने सितंबर में अब तक का सर्वश्रेष्ठ उत्पादन किया

वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में 10.3% उत्पादन वृद्धि हासिल की

(जीएनएस)। मॉयल ने सितंबर 2025 और वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में शानदार परिचालन प्रदर्शन किया। यह प्रमुख मापदंडों में तेज वृद्धि के कारण संभव हुआ।

प्रदर्शन की मुख्य बातें: सितंबर 2025 बनाम सितंबर 2024

सितम्बर माह में अब तक का सर्वश्रेष्ठ उत्पादन 1.52 लाख टन रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 3.8% की वृद्धि दर्शाता है।

अन्वेषणात्मक कोर ड्रिलिंग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। यह 5,314 मीटर तक पहुंच गई, जो 46% की उल्लेखनीय वृद्धि है। यह अपने संसाधन आधार के विस्तार पर मॉयल के गहरे फोकस को दर्शाता है।

तिमाही प्रदर्शनः जुलाई-सितंबर 2025 बनाम जुलाई-सितंबर 2024

अब तक का सर्वश्रेष्ठ दूसरी तिमाही उत्पादन 4.42 लाख टन, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 10.3% अधिक है।

बिक्री बढ़कर 3.53 लाख टन हो गई, जो 18.6% की शानदार वृद्धि है।

21,035 मीटर की अब तक की सर्वश्रेष्ठ दूसरी तिमाही की अन्वेषणात्मक कोर ड्रिलिंग, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 4.1% की वृद्धि दर्शाती है।

इस प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए मॉयल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री अजीत कुमार सक्सेना ने कहाः "प्रमुख मानकों में वृद्धि, मॉयल की अपनी परिचालन उत्कृष्टता को सुदृढ़ करने और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अपनी सभी संचालित खदानों में अन्वेषण पर निरंतर जोर देने के साथ, मॉयल मैंगनीज क्षेत्र में अग्रणी बने रहने के लिए अपने भंडार/संसाधनों को बढ़ाने की अच्छी स्थिति में है।"

वस्त्र मंत्रालय ने हथकरघा, हस्तशिल्प और वस्त्र उत्पादों की घरेलू मांग को बढ़ावा देने के लिए 'स्वदेशी अभियान' शुरू किया

अभियान का उद्देश्य घरेलू मांग को प्रोत्साहित करना और भारतीय वस्त्रों को युवाओं और शहरी उपभोक्ताओं के बीच गर्व, शैली और विरासत के प्रतीक के रूप में पुनः स्थापित करना है

(जीएनएस)। देश में हथकरघा, हस्तशिल्प और वस्त्र उत्पादों की घरेलू मांग को बढ़ावा देने के लिए वस्त्र मंत्रालय स्वदेशी अभियान शुरू कर रहा है। इस अभियान का लक्ष्य और उद्देश्य है:

घरेलू मांग को प्रोत्साहित करना

घरेलू वस्त्र उपभोग में वृद्धि करना, विशेष रूप से शहरी युवाओं और जेन-जी के बीच।

राष्ट्रीय पहचान के रूप में वस्त्र विरासत को शामिल करना

भारतीय वस्त्रों को गर्व और शैली के प्रतीक के रूप में पुनः स्थापित करना, विशेष रूप से युवाओं और शहरी उपभोक्ताओं के बीच।

उत्पादकों और एमएसएमई को सशक्त बनाना

बुनकरों, कारीगरों और वस्त्र एमएसएमई के लिए बाजार पहुंच और आय के अवसरों का विस्तार करना।

आत्मनिर्भर भारत के साथ तालमेल बनाना

वस्त्र उद्योग के लिए पीएलआई, पीएम मित्र पार्क, ओडीओपी जैसी पहलों के साथ अभियान प्रयासों को एकीकृत करना।

संस्थागत खरीद को प्रोत्साहन

मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और शैक्षणिक संस्थानों को वर्दी, साज-सज्जा आदि में भारतीय निर्मित वस्त्रों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।

यह अभियान अगले 6 से 9 महीनों तक पूरे भारत में चलाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य घरेलू उत्पादों की समृद्ध विरासत के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना और उन्हें शिक्षित करना है। इसका उद्देश्य भारतीय वस्त्रों को विशेष रूप से युवाओं और शहरी उपभोक्ताओं के बीच गर्व और शैली के प्रतीक के रूप में पुनः स्थापित करना है। इस दौरान विभिन्न आयोजनों, सामाजिक कार्यक्रमों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जागरूकता पैदा की जाएगी। इस अभियान में विभिन्न राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी अपेक्षित है। स्वदेशी कपड़ा, देश की शान - यही है भारत की पहचान के नारे के साथ यह अभियान चलाया जाएगा।

भारत का वस्त्र और परिधान बाजार 2024 में 179 बिलियन डॉलर का है, जो 7 प्रतिशत से अधिक की औसत वार्षिक वृद्धि दर (एएजीआर) से बढ़ रहा है।

घरेलू बाजार में घरेलू (एचएच) क्षेत्र का योगदान 58 प्रतिशत है और यह 8.19 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ रहा है। इसी समय, गैर-घरेलू खपत घरेलू बाजार का 21 प्रतिशत है और 6.79 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ रहा है।

हालांकि, जीएसटी सुधारों के कारण दरों में हाल में हुए बदलावों से यह उम्मीद की जा रही है कि घरेलू और गैर-घरेलू क्षेत्र में वस्त्र और परिधानों की मांग बढ़ेगी, जिससे देश में वस्त्रों की खपत में वृद्धि दर बढ़ सकती है।

विभिन्न कार्यक्रमों और स्वदेशी अभियानों के कार्यान्वयन के माध्यम से सरकार की निरंतर पहलों से यह उम्मीद की जाती है कि घरेलू मांग प्रति वर्ष 9 से 10 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ेगी और 2030 तक वस्त्रों की कुल घरेलू मांग 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच जाएगी।

"उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) संकलन में मुफ्त पीडीएस वस्तुओं के प्रबंध" पर चर्चा पत्र 2.0 का विमोचन

प्रविष्टि तिथिः 04 डउळ 2025 2:09ढट८ ढक्ह ऊ्

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) का आधार संशोधित कर रहा है। इस प्रक्रिया में मूल्य संग्रहण का दायरा बढ़ाना, मौजूदा पद्धतियों को परिष्कृत करना, नए डेटा स्रोतों की खोज करना और मूल्य संग्रहण एवं सूचकांक संकलन में आधुनिक तकनीक का प्रभावी उपयोग शामिल है।

भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2023 से 75 प्रतिशत ग्रामीण और 50 प्रतिशत शहरी आबादी को कवर करने वाली मुफ्त खाद्यान्न वितरण योजना के अंतर्गत, सीपीआई और मुद्रास्फीति माप में इसके उचित और यथार्थवादी प्रतिबिंब का विषय प्रासंगिक और जरूरी हो गया है।

इस विषय पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, भारतीय रिजर्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अन्य संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं तथा सरकारी संगठनों के साथ विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। इस विषय पर 20 नवंबर, 2024 को एक विचार-मंथन सत्र भी आयोजित किया गया था, जिसके बाद दिसंबर, 2024 में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा पहला चर्चा नोट प्रकाशित किया गया।

चर्चा पत्र 2.0 में प्रस्तावित कार्यप्रणाली, उपर्युक्त चर्चाओं के दौरान प्राप्त सुझावों और प्रतिक्रियाओं को शामिल करने के बाद, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा तैयार की गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, सीपीआई संकलन ढांचे में मुफ्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) वस्तुओं के संबंध में चर्चा पत्र 2.0 पर विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, सरकारी निकायों, राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थानों और अन्य हितधारकों से विचार और टिप्पणियां आमंत्रित करता है। चर्चा पत्र 2.0 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट www.mospi.gov.in और सीपीआई वेबहाउस www.cpi.mospi.gov.in पर उपलब्ध है। टिप्पणियां और सुझाव 22 अक्टूबर, 2025 तक psd-nso2020@mospi.gov.in पर भेजे जा सकते हैं।

डॉ. मनसुख मांडविया विश्व शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के विशेष संस्करण की शोभा बढ़ाएंगे

(जीएनएस)।

फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल 5 अक्टूबर को मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में अपने भव्य विश्व शिक्षक दिवस संस्करण के लिए तैयार है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे तथा साइकिल रैली में सैकड़ों शिक्षकों, विद्यार्थियों और नागरिकों का नेतृत्व करेंगे। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल स्वास्थ्य और दीर्घकालिक समय के लिए एक जन आंदोलन बन गया है।

डॉ. मांडविया ने कहा, "आइए इस विश्व शिक्षक दिवस पर हम अपने उन गुरुओं का स्मरण करें जिन्होंने राष्ट्र को आकार दिया। मैं प्रत्येक नागरिक, युवा और वृद्ध से आग्रह करता हूँ कि वे कल के फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल में शामिल हों। हम स्वस्थ और फिट रहने तथा एक अधिक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प लें।"

कल के कार्यक्रम में निम्न लिखित एथलीट और फिटनेस इन्फ्लुएंसर शामिल होंगे:

सचिन यादव, भारत के उभरते हुए भाला फेंक खिलाड़ी, जिन्होंने 2025 एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक जीता और टोक्यो में 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में चौथे स्थान पर रहे।

तानिया सचदेव, अंतर्राष्ट्रीय मास्टर (आईएम) और महिला ग्रैंडमास्टर (डब्ल्यूजीएम), दो बार की भारतीय महिला शतरंज चैंपियन और लोकप्रिय शतरंज कमेंटेटर।

अभिषेक नैन, ओलंपिक कांस्य पदक विजेता (पेरिस 2024), 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता और 2022 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता एवं भारत की एशिया कप 2025 विजेता हॉकी टीम के प्रमुख सदस्य।

रोहताश चौधरी, जिन्हें 'पुश-अप मैन ऑफ इंडिया' के नाम से जाना जाता है।

शिक्षा विभाग, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, लेडी श्रीराम कॉलेज के प्रतिनिधियों तथा नागरिकों सहित लगभग 1000 प्रतिभागियों के कल साइकिल अभियान में भाग लेने की उम्मीद है।

फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का 5 अक्टूबर का संस्करण शिक्षकों को समर्पित है जो युवाओं और भविष्य के चैंपियनों को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, साथ ही फिट इंडिया के आदर्श वाक्य "एक घंटा रोज, खेल के साथ" को बढ़ावा देता है।

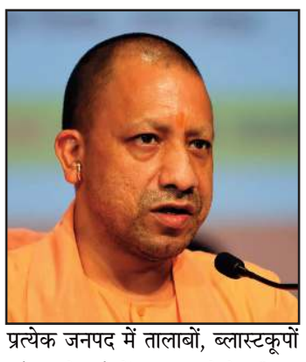

प्रत्येक जनपद में तालाबों, ब्लास्टकूपों और चेकडैमों का फोटोग्राफिक डॉक्यूमेन्टेशन कराया जाए। जनता को जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अभियान चलाया जाए। जल संरक्षण और भूजल रिचार्जिंग को लेकर प्रदेश सरकार का संकल्प अटल है और इसे समाज की भागीदारी से एक सफल मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा : सीएम योगी आदित्यनाथ

डबल इंजन सरकार विरासत का सम्मान करेगी, विकास करेगी और आपकी सुरक्षा करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। आने वाली पीढ़ी के लिए विकसित उत्तर प्रदेश एक नये अभियान के साथ आगे बढ़ा है... उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर होगा तो विकसित भी होगा, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप भी 'समर्थ उत्तर प्रदेश' पोर्टल पर क्यूआर कोड को स्कैन करते हुए अपने सुझाव भेज सकते हैं... सीएम योगी आदित्यनाथ

'नौकरी' मौत बनी! अमेरिका में भारतीय छात्र का दर्दनाक अंत, गैस स्टेशन पर किसने और क्यों मारी गोली?

(जीएनएस)।

अमेरिका में उच्च शिक्षा प्राप्त करने गए भारतीय छात्रों की सुरक्षा पर एक बार फिर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। हाल ही में, तेलंगाना के हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले 27 वर्षीय भारतीय छात्र चंद्रशेखर पोले की डलास, अमेरिका में गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह दुखद घटना शुक्रवार रात को उस समय हुई, जब पोले एक गैस स्टेशन पर पार्ट-टाइम काम कर रहे थे।

एक अज्ञात हमलावर ने उन्हें गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पोले के परिवार में बेटे की मौत की खबर सुनने के बाद मातम पसरा हुआ है, और उन्होंने तेलंगाना तथा भारत सरकार से उनके पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द घर लाने में मदद की गुहार लगाई है।

जांच जारी, 'ूस्टन वाणिज्य दूतावास सक्रिय

'ूस्टन स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास (CGI) ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। वाणिज्य दूतावास ने बताया कि वे पोले के परिवार के साथ लगातार संपर्क में हैं और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। स्थानीय अमेरिकी

अधिकारियों के साथ मिलकर मामले की जांच की निगरानी की जा रही है, ताकि हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। पोले 2023 में अमेरिका में मास्टर डिग्री हासिल करने गए थे और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद फिलहाल पूर्णकालिक नौकरी की तलाश में थे। इसी दौरान, वह अपनी आजीविका चलाने के लिए गैस स्टेशन पर पार्ट-टाइम काम कर रहे थे।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी चंद्रशेखर पोले की दुखद मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन देते हुए कहा कि यह घटना अत्यंत दुखद और चौंकाने वाली है। इसी बीच, इफ्र विधायक सुधीर रेड्डी और पूर्व मंत्री टी. हरीश राव ने शनिवार को पोले के हैदराबाद स्थित आवास पर जाकर शोक संतप्त परिवार से मुलाकात की। हरीश राव ने सोशल मीडिया के माध्यम से राज्य सरकार से आग्रह किया कि चंद्रशेखर के पार्थिव शरीर को भारत लाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। फिलहाल, डलास काउंटी मेडिकल एग्जामिनर का कार्यालय अभी तक मृत्यु प्रमाणपत्र जारी नहीं कर पाया है, जो शव को भारत लाने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।

अमेरिका में भारतीय छात्रों की सुरक्षा पर बढ़ती चिंता

यह डलास की घटना अमेरिका में पार्ट-टाइम नौकरी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर चिंता का विषय बन गई है, खासकर उन छात्रों के लिए जो देर रात की शिफ्टों में काम करते हैं। पिछले कुछ महीनों में भारतीय छात्रों पर हमलों की कई घटनाएं सामने आई हैं। इसी साल जनवरी में, तेलंगाना के एक 26 वर्षीय छात्र की कनेक्टिकट में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और रंगा रेड्डी के एक व्यक्ति की भी इसी तरह मौत हुई थी। पिछले महीने, महबूबनगर जिले के एक टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल की कैलिफोर्निया में पुलिस की गोली से मृत्यु हो गई थी। इन घटनाओं ने विदेशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर लगातार बढ़ रहे सवालों को जन्म दिया है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत का ऑनलाइन लघु अवधि इंटर्नशिप कार्यक्रम- सितंबर 2025 का समापन

21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 74 विश्वविद्यालय के छात्रों ने इसे सफलतापूर्वक पूरा किया।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की सदस्य, श्रीमती विजया भारती सयानी ने अपने समापन भाषण में युवाओं से सतर्क रहने, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और अधिक समावेशी एवं समतावादी समाज के निर्माण में योगदान का आग्रह किया।

(जीएनएस)।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने 2025-2026 के अपने तीसरे ऑनलाइन लघु अवधि इंटर्नशिप कार्यक्रम (ओएसटीआई) का सफलतापूर्वक समापन किया, जिसमें 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 74 विश्वविद्यालय के छात्रों ने भाग लिया। इस ओएसटीआई का उद्घाटन महासचिव श्री भरत लाल ने 22 अगस्त, 2025 को किया था।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सदस्य श्रीमती विजया भारती सयानी ने मुख्य अतिथि के तौर पर समापन सत्र को संबोधित करते हुए प्रशिक्षुओं को दो सप्ताह इस इंटर्नशिप कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए बधाई दी और उनके समर्पण की सराहना की। उन्होंने न्याय और समानता के संरक्षक के रूप में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की भूमिका पर जोर देते हुए, महिला अधिकार, बाल संरक्षण, मानसिक स्वास्थ्य, हिरासती न्याय और हाशिए पर रह रहे समुदायों के सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में आयोग के कार्यों का उल्लेख किया।

मनोविज्ञान, फोरेंसिक विज्ञान, व्यवसाय और मानवाधिकार जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञों के प्रभावशाली सत्रों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए श्रीमती विजया भारती सयानी ने प्रदान की गई शिक्षा की सराहना की। उन्होंने प्रेरक उदाहरणों का हवाला देते हुए प्रशिक्षुओं से मानवीय गरिमा के सक्रिय रक्षक बनने, अपने ज्ञान का उपयोग सामाजिक भलाई के लिए करने और व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक, दोनों क्षेत्रों में संवैधानिक सिद्धांतों को बनाए रखने का आग्रह किया। उन्होंने युवाओं से सतर्क रहने, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने और एक अधिक समावेशी एवं समतामूलक समाज के निर्माण में योगदान देने का आ'ान किया।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की संयुक्त सचिव श्रीमती सैदिंगपुई छकछुआक ने इंटर्नशिप रिपोर्ट प्रस्तुत की। मानव अधिकार आयोग के सदस्यों, वरिष्ठ अधिकारियों, विशेषज्ञों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों द्वारा मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर आयोजित सत्रों के अलावा, प्रशिक्षुओं को दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल, पुलिस स्टेशन और आशा किरण आश्रय गृह का आभासी भ्रमण भी कराया गया। उन्हें विभिन्न सरकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली, मानव अधिकारों की रक्षा के तंत्र, जमीनी हकीकत और समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक कदमों की जानकारी दी गई। इस दौरान पुस्तक समीक्षा, समूह शोध परियोजना प्रस्तुति और भाषण प्रतियोगिता के विजेताओं की भी घोषणा की गई।

इस अवसर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संयुक्त सचिव श्री समीर कुमार और निदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल वीरेंद्र सिंह उपस्थित थे।

ओएसटीआई विभिन्न शैक्षणिक क्षेत्रों के छात्रों को मानव अधिकारों के प्रमुख मुद्दों को समझने और उनका समाधान करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। व्यावहारिक शिक्षण और संवादात्मक चर्चाओं के माध्यम से, प्रतिभागी अंतर्राष्ट्रीय कानून, भारत में मानव अधिकारों की चिंताओं और व्यावहारिक तरीकों का अध्ययन करते हैं।

डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका, कोर्ट ने पलटा फैसला, अमेरिकी राष्ट्रपति पर लगाया गंभीर आरोप

(जीएनएस)।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शनिवार को एक बड़ा कानूनी झटका लगा, जब एक संघीय अदालत ने ओरेगन के पोर्टलैंड शहर में 200 नेशनल गार्ड सैनिकों की तैनाती के उनके आदेश पर तत्काल रोक लगा दी।

यह अंतरिम आदेश स्वयं ट्रंप द्वारा नियुक्त यूएस डिस्ट्रिक्ट जज करिन इम्मरगट ने दिया। जज ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि ट्रंप प्रशासन यह साबित करने में विफल रहा कि पोर्टलैंड में हो रहे विरोध प्रदर्शन "विद्रोह" के स्तर पर पहुँच गए थे या वे कानून-व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा थे, जिसके कारण नेशनल गार्ड

प्रशासन की दलील बनाम ओरेगन की स्वायत्तता

ओरेगन की अटॉर्नी जनरल डैन रेफील्ड ने ट्रंप प्रशासन के इस कदम को अदालत में चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि राष्ट्रपति अपनी आप्रवासन (इमिग्रेशन) नीतियों के खिलाफ होने वाले शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को

जानबूझकर बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहे हैं, जिसका एकमात्र उद्देश्य नेशनल गार्ड पर गैरकानूनी नियंत्रण स्थापित करना है। राज्य सरकार ने इसे राज्य की स्वायत्तता पर हमला और संघीय कानून का उल्लंघन बताया। याचिका में यह भी कहा गया कि ट्रंप ने यह निर्णय संभवतः 2020 के पुराने, हिंसक प्रदर्शनों के वीडियो देखकर लिया, जबकि इस बार के प्रदर्शन "छोटे और शांतिपूर्ण" थे। वकीलों ने बताया कि जून के मध्य के बाद से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जो शांतिपूर्ण माहौल का संकेत है।

घरेलू आतंकवाद या राजनीतिक दखल?

ट्रंप प्रशासन का पक्ष है कि नेशनल गार्ड की तैनाती "घरेलू आतंकवाद" से संघीय इमारतों की रक्षा करने के लिए आवश्यक है। हालांकि, विपक्षी डेमोक्रेटिक नेताओं ने इसे राजनीतिक दखल और राष्ट्रपति द्वारा शक्ति का दुरुपयोग बताया है। व्हाइट हाउस ने संकेत दिया है कि वह इस फैसले के खिलाफ अपील करेगा।

पोर्टलैंड में फिर से हुआ प्रदर्शन

इसी बीच, शनिवार शाम को भी पोर्टलैंड में कइए मुख्यालय के बाहर प्रदर्शनकारी एकत्र हुए। हालांकि उन्होंने सुरक्षा बलों के खिलाफ नारेबाजी की, पुलिस के अनुसार, स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रही। यह फैसला राष्ट्रपति और राज्य सरकारों के बीच संघीय शक्ति के संतुलन पर एक महत्वपूर्ण कानूनी बहस को रेखांकित करता है।

बिहार विस चुनाव 2025 भाजपा मेनिफेस्टो बनेगा खास, 1 करोड़ लोगों के सुझाव से होगा तैयार, 20 अक्टूबर तक भेजें राय

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मी तेज हो चुकी है। राजनीतिक दल एक-एक कर अपने चुनावी वादों और रणनीतियों को जनता के बीच ला रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इस बार अपने घोषणा पत्र यानी मेनिफेस्टो को लेकर बड़ा ऐलान किया है।

भाजपा का कहना है कि आने वाले चुनाव में उसका मेनिफेस्टो महज नेताओं की सोच पर नहीं, बल्कि जनता की राय और सुझावों पर आधारित होगा। दावा है कि करीब 1 करोड़ लोगों से सुझाव लेकर 5 साल का रोडमैप तैयार किया जाएगा।

5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक चलेगा अभियान

भाजपा नेताओं ने शनिवार (04 अक्टूबर) को पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक राज्यभर में एक विशेष अभियान चलेगा। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों से राय मांगेंगे। किसानों से लेकर महिलाओं तक, युवाओं से लेकर मजदूरों तक-हर वर्ग को इसमें शामिल करने की योजना है।

मंत्री प्रेम कुमार ने कहा, "यह बिहार के इतिहास में पहली बार है जब कोई दल जनता से सीधे राय लेकर मेनिफेस्टो तैयार करेगा। यह चुनावी दस्तावेज नहीं बल्कि जनता का एजेंडा होगा।"

हर जिले में सुझाव पेटियां और LED रथ

पार्टी ने घोषणा की है कि सभी 38 जिलों में करीब 3 हजार सुझाव पेटियां लगाई जाएंगी। लोग इनमें लिखकर अपने विचार डाल सकेंगे। इसके साथ ही भाजपा पूरे बिहार में छएऊ चुनाव रथ भी रवाना करेगी, जो गांव-गांव जाकर अभियान चलाएंगे और लोगों

को जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे।

दफकोड से लेकर व्हाट्सएप तक पर दे सकते हैं सुझाव

भाजपा ने इस अभियान को हाईटेक भी बनाया है। हर चौक-चौराहे पर दफ कोड लगाए जाएंगे, जिन्हें स्कैन कर लोग सुझाव भेज सकेंगे।

एक नया व्हाट्सएप नंबर (8980243243) लॉन्च किया गया है। पार्टी की नई वेबसाइट भी आज 05 अक्टूबर से एक्टिव होगी, जहां ऑनलाइन सुझाव दर्ज किए जा सकेंगे।

मिस्ड कॉल, पत्र और फोन के जरिए भी राय देने का विकल्प रहेगा। पार्टी नेताओं का कहना है कि "जितने ज्यादा सुझाव आएंगे, उतना ही बेहतर और मजबूत घोषणा पत्र बनेगा।"

अक्टूबर में होंगे विशेष कार्यक्रम

भाजपा ने सिर्फ सुझाव इकट्ठा करने तक ही अभियान सीमित नहीं रखा है। अक्टूबर महीने भर खास कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिनमें जनता को सीधा जोड़ा जाएगा।

8 अक्टूबर - हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस

9 अक्टूबर - युवा सम्मेलन

10 अक्टूबर - महिला सम्मेलन

11-12 अक्टूबर - हर घर तक पहुंचेंगे भाजपा कार्यकर्ता

14 अक्टूबर - उद्यमिता सम्मेलन

इन आयोजनों के जरिए पार्टी यह संदेश देना चाहती है कि उसका मेनिफेस्टो सभी वर्गों की उम्मीदों को शामिल करेगा।

"जनता तय करेगी आने वाले 5 साल की दिशा"

राज्यसभा सांसद मनन मिश्रा ने कहा, "यह कोई साधारण चुनावी वादा नहीं है। इस बार घोषणा पत्र तय करेगा कि बिहार के अगले 5 साल कैसे होंगे। हम जनता से अपील करते हैं कि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने विचार भेजें। इस अभियान में जितना बड़ा जनसहभाग होगा, उतना ही मजबूत भविष्य का रोडमैप बनेगा।"

क्यों खास है यह घोषणा?

आमतौर पर राजनीतिक दलों का घोषणा पत्र नेताओं और थिंक टैंक के बीच बैठकर तैयार होता है। लेकिन भाजपा ने इसे जनता की आकांक्षाओं का दस्तावेज बनाने की पहल की है। ग्रामीण इलाके से लेकर शहरी युवाओं तक, हर वर्ग को इसमें अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। पार्टी का मकसद साफ है-वह अपने मैनिफेस्टो को सिर्फ चुनावी 'जुमला' नहीं बल्कि जनता का साझा एजेंडा बनाना चाहती है।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भाजपा का यह नया प्रयोग कितना सफल होता है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि '1 करोड़ सुझावों से बना मैनिफेस्टो' जनता के बीच चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। अब देखना होगा कि लोग कितनी संख्या में इस अभियान से जुड़ते हैं और भाजपा इन रायों को अपने घोषणा पत्र में किस तरह शामिल करती है।

लूट करके चलती ट्रेन से कूद जाता था ज्ञानेंद्र शुक्ला

बाराबंकी जीआरपी पुलिस ने सराहनीय कार्य किया, लखनऊ पुलिस द्वारा ट्रेनों के दरवाजे के पास की सीटों पर बैठे यात्रियों का सामान पैसे , बैग,मोबाइल गले की चेन छीन कर चलती ट्रेन से कूद जाता था अपर पुलिस महानिदेशक के आदेशानुसार श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ रोहित मिश्रा के निर्देशन में ट्रेनों पर चोरी ,लूट, जहरखुरानी जैसी घटनाओं की रोकथाम वह यात्रियों के सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है , इसी क्रम में दि. 4 /10/ 025 प्लेटफार्म नंबर 1 अयोध्या आउटर रेलवे अस्पताल गेट के पास सीमेंट बेंच पर बाराबंकी जीआरपी पुलिस ने ज्ञानेंद्र शुक्ला को गिरफ्तार किया, पूछ-ताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि , घटना करने से पूर्व भीड़भाड़ वाली ट्रेनों को चिन्हित कर चलती ट्रेनों वा प्लेटफार्म पर खड़ी ट्रेनों पर

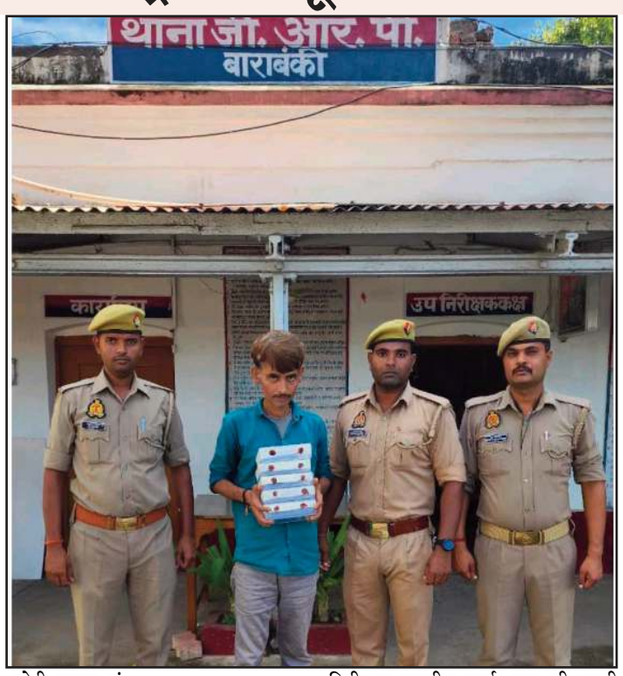

चोरी करता हूं

यही मेरी जीवकपार्जन का धंधा है , गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक रजनीश वर्मा थाना जीआरपी अनुभाग लखनऊ हे. कांस्टेबल अरुण कुमार थाना जीआरपी जितेंद्र कुमार इंद्रजीत क. मिलिंद कुमार आदि टीम पकड़ने में सम्मिलित थी।

पीलीभीत के सखिया गांव में अवैध मेले का प्रशासन ने किया निषेध

(जीएनएस)।

पीलीभीत, 4 अक्टूबर 2025: बीसलपुर तहसील के सखिया गांव में 19 जुलाई से बिना प्रशासन की अनुमति अवैध रूप से मेला आयोजित किया जा रहा था, जिसे शनिवार को प्रशासन ने बंद करा दिया। कई माह तक चले इस मेले में दूर-दराज के लोग आते थे और भारी चढ़ावा जमा होता था। मेले के आयोजकों ने इसे चमत्कारी बताया और दावा किया कि यहां आने वाले लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं।

गांव में मेला होने से न केवल धार्मिक भावनाओं का अनुचित लाभ उठाया जा रहा था, बल्कि बीसलपुर-बेनिपुर मार्ग पर भी अक्सर जाम लगने की समस्या उत्पन्न हो गई थी।